

## मई दिवस : दुनिया के मजदूरों एक हो!

1 मई दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दिन है जो मजदूरों को एकजुटता और संघर्ष की प्रेरणा देता है। यह हमें उस महान संघर्ष की याद दिलाता है, जब अमेरिका के साथ ही पूरे यूरोप में मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था और उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। इसके खिलाफ अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई, 1886 को भीषण संघर्ष हुआ। यह संघर्ष चार दिनों तक चला और इसमें मजदूरों के खून से धरती लाल हो गई। पर मजदूरों का यह संघर्ष रंग लाया और उनके काम के घंटे निर्धारित हो गए। कार्यदिवस 8 घंटे का तय हुआ। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में मई दिवस एक श्रमि त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह मजदूरों को उनके ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है। यह ठीक है कि दुनिया भर में मजदूरों ने अपने संघर्ष की बदौलत कई जीतें हासिल की हैं, पर आज 21वीं सदी में जब दुनिया भर में मजदूरों का राज स्थापित हो जाना चाहिए था, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का अंत हो जाना चाहिए था और समता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए थी, वहीं देखने में आ रहा है कि डेढ़ सौ साल पहले ही मजदूरों ने जो अधिकार हासिल किए थे, वो भी अब उनसे छीने जा रहे हैं। यद्यपि यह पूंजीवादी व्यवस्था का मरण काल है, पर अभी भी यह काफी मजबूत दिख रहा है।

यही कारण है कि आज मजदूरों से मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है। हमारे देश में टेका प्रथा के तहत मजदूरों का अकथनीय शोषण हो रहा है। काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं। कम से कम मजदूरी पर लोग 12 से 14 घंटे तक फैक्ट्रियों में पसीना बहाने को मजबूर हैं। फिर भी उनके साथ हर तरह के जुल्म हो रहे हैं। असंगठित मजदूरों की हालत और भी खराब है। भारत के साथ ही पूरी दुनिया में मजदूरों का आंदोलन पिछड़ता चला जा रहा है। प्रतिक्रियावादी ताकतें हर जगह सत्ता पर काबिज हैं। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है। मजदूरों ने अपने संघर्ष से जो कुछ भी हासिल किया था, आज उसे वो खो देने की हालत में आ गए हैं। सवाल है कि ऐसी हालत में क्या करें। देखने में आ रहा है कि अब मजदूर यूनियन जो बड़े राजनीतिक दलों से जुड़ी रही हैं, चाहे वो वामपंथी हों या मध्यममार्गी, मजदूरों के हित के लिए कुछ भी सार्थक कर पाने में अक्षम रही हैं। उनके संघर्ष की कोई राजनीतिक दिशा भी नहीं है। जब तक मजदूरों के संघर्ष की कोई स्पष्ट राजनीतिक दिशा नहीं होगी तब तक उन्हें कुछ खास हासिल भी नहीं हो सकता। आज जितने ट्रेड यूनियन हैं, वो मजदूरों को संघर्ष की सही दिशा से भटकाने में लगे हैं और फैक्ट्री मालिकानों के एजेंट के रूप में सामने आ रहे हैं। उनकी कोई राजनीतिक लाइन नहीं है। ऐसे में, मजदूरों के लिए कोई सही राह नहीं मिल सकती। आज स्थिति ये है कि देश में दक्षिणपंथी शक्तियां केंद्र की सत्ता में आ चुकी हैं। केंद्र सरकार मजदूर, किसान विरोधी कानून बना रही है। मोदी सरकार ने जो श्रम कानून बनाए हैं या उनमें संशोधन किया है, वह पूरी तरह मजदूर विरोधी है। पर इन कानूनों का देशव्यापी एवं प्रभावी विरोध नहीं हो रहा है।

मई दिवस को एक रस्मअदायगी समझ लेना या त्योहार की तरह मना लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस दिवस को संघर्ष के संकल्प दिवस के रूप में मनाना होगा और संगठन का नया ढांचा तैयार करना होगा। वर्तमान ढांचे पुराने पड़ गए हैं। ज्यादातर मजदूर यूनियनों का नेतृत्व भ्रष्ट हो गया है और मालिकानों से मिल चुका है। इस भ्रष्ट ढांचे को तोड़ कर जब मजदूर वैचारिक आधार पर संगठित होंगे और उनके बीच से नेतृत्व निकलेगा, तो वही मजदूर वर्ग के संघर्षों को एक नए अंजाम तक ले जा सकता है। यह समय की चुनौती है और इसे स्वीकार करना ही होगा। मार्क्स, एंगेल्स के इस नारे को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। श्रुनिया के मजदूरों एक हो।

## मई दिवस का संदेश

हम मेहनतकश जगवालों से

जब अपना हिस्सा मांगेंगे

इक खेत नहीं इक देश नहीं

हम सारी दुनिया मांगेंगे

यां सागर-सागर मोती हैं

या परबत-परबत हीरे है

ये सारा माल हमारा है

हम सारा खजाना मांगेंगे

जो खून बहा जो बाग उजड़े

जो गीत दिलों में क्रल्ल हुए

हर क्रतरे का हर गुंचे का

हर गीत का बदला मांगेंगे

ये सेठ ब्यौपारी रजवाड़े दस लाख

तो हम दस लाख करोड़

ये कितने दिन अमरीका से

जीने का सहारा मांगेंगे

जब सफ़ सीधी हो जायेगी

जब सब झगड़े मिट जायेंगे

हम हर इक देश के झंडे

पर इक लाल सितारा मांगेंगे

-फ़ैज़

## मन्त्री पद को तरसते विधायक बेचारे

फ़रीदाबाद ( म.मो. ) फ़रीदाबाद-पलवल ज़िले से 9 विधायक हैं और मन्त्री एक भी नहीं। इसी ज़िले से कभी दो-दो, तीन-तीन मन्त्री भी रह चुके हैं। इस लिये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब भी मन्त्रिमंडल विस्तार का शिगूफ़ा छोड़ते हैं तो यहाँ के (भाजपा) विधायकों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। राजनीति को समझने वाले बखूबी समझते हैं कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो वह अपने मन्त्रिमंडल का विस्तार करने की अपेक्षा शिगूफ़े ज्यादा छोड़ता है। इससे मन्त्री पद को तरसते बेचारे विधायकों की आस बंधी रहती है। वे अपने आप को मुख्यमंत्री का अधिक से अधिक वफ़ादार साबित करने की होड़ में जी-जान से जुटे रहते हैं। और एक बार विस्तार हो गया तो फिर कोई आस बाकी नहीं रहती। इसलिये अधिक काईयां मुख्यमंत्री पूरा विस्तार कभी नहीं करते। वे एक दो सीट सदैव बचाकर ही रखते हैं ताकि बेचारों की आस जड़-मूल से समाप्त न होवे।

इस ज़िले के 9 विधायकों में से भाजपा के केवल 3 ही हैं, इसलिये मुकाबला भी इन्हीं में से हो सकता है। बल्लबगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा को इसलिये रस में नहीं माना जाता क्योंकि उनके सगे समधी

रामबिलास शर्मा पहले से ही कई महत्वपूर्ण एवं भारी-भरकम मन्त्रालय कब्ज़ाये हुए हैं तथा मूलचंद को साथे रखना भी उन्हीं के जिम्मे है।

बाकी बचे दो-विपुल गोयल और सीमा त्रिखा। अब असली मुकाबला इन दोनों के बीच ही बनता है। यह मुकाबला दीये और तूफ़ान के बीच जैसा लगता है। भाजपा विधायक दल के प्रबलतम धनपशुओं में से कैप्टेन अभिमन्यु के बाद कोई ठहरता है तो वह है विपुल गोयल। बिना विधायक बने ही जिसने लूट-कमाई के बड़े अम्बार लगा लिये हों तो मन्त्री पद मिलने के बाद तो वह गज़ब ही ढा देगा। जाहिर है ऐसे में वह पार्टी व संघ की भी पर्याप्त 'सेवा-पानी' कर पायेगा। अखबारों में बार-बार बयान छपवाने के बावजूद बेशक शहर की गलियों-सड़कों से वे कुत्तों और गावों को नहीं हटवा सकें तो क्या हुआ, दो बार नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में तमाशा तो करवा ही चुके हैं। और फिर सबसे बड़ा काम जो कोई भी विधायक नहीं कर पाया वह उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को लहरा कर पूरा कर दिया। 250 फ़ीट ऊंचा झंडा गार कर उन्होंने देश के 'गौरव' को रसातल से उठा कर 250 फ़ीट ऊंचा तो कर ही दिया। जब नवीन ज़िंदल मात्र 100-100 फ़ीट

ऊंचे झंडे लहरा कर 10 वर्ष तक इस देश को लूट सकता है तो बेचारे विपुल ने क्या गुनाह कर रखा है? लूट का एक अच्छा मौका पाने का हक तो उनका भी बनता ही है।

वैसे पूरे ज़िले (फ़रीदाबाद-पलवल) के वासियों को इसके लिये चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह वहम पालने की भी कोई जरूरत नहीं है कि ज़िले को मन्त्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने से उनका कोई भला होने वाला है। गत हुड्डा राज में अकेले फ़रीदाबाद से महेन्द्रप्रताप सिंह, शिवचरण लाल व बल्लबगढ़ से शारदा राठौर मन्त्रिमंडल में शामिल थे।

पलवल से विधायक न होते हुए भी कर्ण दलाल वहां बतौर मुख्यमंत्री ही काम करते थे। इस सबके बावजूद आम जनता को क्या मिला? उनठन गोपाल। तमाम सरकारी स्कूलों व अस्पतालों की दुर्दशा, राशन डिपो से लेकर बिजली, थाना व तहसील आदि हर सरकारी दफ़्तर में जनता की लूट खुलेआम सरकारी संरक्षण में जारी थी। इसलिये ज़िले से मन्त्री चाहे कोई भी बने जनता का शोषण व उत्पीड़न ज्यों का त्यों जारी रहेगा। हां मन्त्री पद पाने वाले के ज़रूर पौ बारह हो जायेंगे।

## टेका-कर्मियों के साथ भेदभाव के खिलाफ़ एक लड़ाई

-श्यामल कुमार

देश की समस्यायें में सबसे अहम समस्या बेरोज़गारी है। सरकार इस समस्या को खत्म करना तो दूर, इस पर बात करने से भी कतराती है। आज हर क्षेत्र में सरकार टेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। आज से 44 साल पहले देश की संसद ने टेका मजदूर (संचालन एवं उन्मूलन) कानून 1970 बनाया था। तब सरकार ने यह माना था कि टेका मजदूरों की भर्ती के चलते कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिये ही यह कानून बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने त्रिपक्षीय कमेटियों (सरकार-मालिक-मजदूर) की सिफ़ारिश व आम राय से यह माना था कि-

1. जहां कहीं भी सम्भव है, टेका मजदूरों द्वारा किये जा रहे काम को ही समाप्त कर दिया जाय।

2. जहां कहीं यह सम्भव न हो, वहां टेका मजदूर से काम लिया जाय, वेतन अदायगी व अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाय।

इन दोनों कामों को लागू करवाने की जिम्मेदारी केन्द्र व राज्य सरकारों के अधीन काम करनेवाले श्रम विभाग की थी। परन्तु सरकार और श्रम विभाग ने इस कार्य को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया है।

इस कानून के बनने के 44 वर्षों का अनुभव यही है कि सरकार ने टेका मजदूरों के संचालन व उन्मूलन की दिशा में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए। उल्टा सरमायादारों के हक में इस प्रथा को गन रूप से बढ़ावा दिया गया। 1990 के बाद से नवउदारवादी नीतियों के तहत इसमें और तेज़ी आयी है।

शर्म की बात तो यह है कि निजी कारखानों/संस्थानों के इस खेल में सरकारें भी शामिल हो गयी हैं। सरकारी क्षेत्र में होनेवाले कार्य का 70 से 80 प्रतिशत टेका मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि सार्वजनिक इकाईयों, सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग, एमसीडी इत्यादि में डॉक्टरों, शिक्षकों, ड्राइवों, कन्डक्टरों व कर्मचारियों की स्थायी पदों पर भर्ती न करके साल दर साल टेके पर भर्ती की जा रही है।

इंडियन स्टार्किंग फ़ेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे देश में लगभग 1 करोड़ 23 लाख लोग सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, जिनमें 69 लाख लोग केवल टेके पर काम कर रहे हैं। सरकार मानती

है कि टेका मजदूरों को समान काम करने के बावजूद समान वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यही असमान व्यवहार विद्रोह की ओर मजदूरों को संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, जिसके गम्भीर परिणाम आये दिन देखने को मिलते हैं। मारुति उद्योग, गुडगांवा में एक प्रबन्धक की मौत, उस घटना के बाद 147 मजदूरों को जेल में बंद कर दिया जाना और उस औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ता असन्तोष इसका एक उदाहरण है। उसके बाद सड़क से लेकर संसद तक भारी हंगामे के बाद तत्काल सरकार ने हस्तक्षेप किया चीफ़ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) ने 23 जनवरी 1913 को एक सरकुलर सभी मंत्रालयों को जारी किया, जिसके तहत-

अगर कोई टेका कर्मी अपने प्रधान नियोक्ता के स्थायी कर्मी के बराबर कार्य करता है, तो टेकेदार द्वारा नियुक्त टेका कर्मी का वेतन, छुट्टी और सेवा शर्तें उस संस्था के प्रधान नियोक्ता के वर्कर के बराबर होंगी।

इस सरकुलर में टेका मजदूर (संचालन एवं उन्मूलन) कानून 1970, और उसके केन्द्रिय नियम के तहत उल्लंघन करनेवाले पर कानूनी कारवाई करने की बात जोर देकर कही गयी।

यह सरकुलर सभी केन्द्रिय मंत्रालयों के साथ ही साथ चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को भी भेजा गया। रेलवे बोर्ड ने भी अपने एक सरकुलर के माध्यम से चीफ़ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के सरकुलर को एमडी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) सहित अपने सभी विभागों को भेजकर इस सरकुलर का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। लेकिन बात आयी-गयी हो गयी।

पिछले दिनों आईटी सेन्टर, आईआरसीटीसी, नई दिल्ली के टेका कर्मियों ने जिनका काम अपने प्रधान नियोक्ता के स्थायी कर्मियों के समान था, इस भेदभाव के खिलाफ़ कदम उठाया। आईटी सेन्टर में केवल 57 आईआरसीटीसी (प्रधान नियोक्ता) के अपने कर्मी हैं, जबकि लगभग 265 टेका कर्मी (टेकेदार द्वारा रखे गये) पिछले 3 वर्षों से भीअधिक समय से कार्यरत हैं। इनमें कई लोग तो पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से टेके पर काम कर रहे हैं। कर्मियों को जानकारी दिये बिना समय-समय पर टेकेदार बदल-बदलकर रिकार्ड में हेराफेरी कर, आईआरसीटीसी (प्रधान

नियोक्ता) द्वारा उन्हें ग्रेच्युटी से वंचित रखा जाता है। साथ ही, एक तरफ़ तो अपने कर्मियों को आईआरसीटीसी हर महीने 40,000 रुपये वेतन व अन्य सुविधाएं देती है, जबकि समान योग्यता और अनुभव होने के बावजूद टेका कर्मियों को सिर्फ़ 11,000-12,000 रुपये मासिक भुगतान करती है। यहां के ज्यादातर टेकाकर्मियों के पास पीएफ़ खाता नहीं है और जिसके पास है भी उनका नियोक्ता के हिस्से का अंश और उनका अपना अंश, दोनों उन्हीं के वेतन से काटा जाता है। ईएसआई की सुविधा के लिये भी नियोक्ता अपना अंश नहीं देता। इसके किस्त की कटौती टेका कर्मियों से ही की जाती है। 300 कर्मचारी होने के बावजूद वहां न तो साफ़ पीने का पानी, न अलग से कोई विश्राम गृह, न महिला कर्मियों के बच्चों के लिये पालना घर और न ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है। यह टेका मजदूर (संचालन एवं उन्मूलन) कानून 1970, का घोर उल्लंघन है। इतना सब कुछ टेकेदार के कर्मी चुपचाप सहने को विवश थे। उनका भविष्य अंधकारमय और निराशजनक लगने लगा था।

आईआरसीटीसी के 125 टेका कर्मियों ने टेका मजदूर कानून 1970 के तहत समान काम के लिये समान वेतन की लड़ाई छेड़ दी। पहले उन्हीं विभाग के स्तर पर ज्ञापन दिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि टेकेदार ने इन टेकाकर्मियों को अगुआई करनेवाले सुरजीत श्यामल को सेवा खराब होने का बहाना करके नौकरी से निकाल दिया, जबकि उन्हें विभाग की ओर से अच्छे काम के लिये मेरिट अवार्ड मिल चुका है। अगले कदम के रूप में टेका कर्मियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भारत सरकार आईआरसीटीसी और टेकेदारी को नाटिस जारी किया है। 4 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया है।

टेका कर्मियों के साथ भेदभाव और उनका अमानवीय शोषण आज हर विभाग में, हर कार्यालय में आम बात है। देश-भर में अलग-अलग विभागों के टेका कर्मियों का आन्दोलन भी चलता रहता है। इस कानूनी लड़ाई का फ़ैसला क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन संगठित प्रतिरोध की दिशा में उठाया गया इन नौजवानों का कदम साहसिक, सरहनीय और उम्मीद जगानेवाला है।